RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

INDORE 01 DECEMBER TO 07 DECEMBER 2021 प्रति बुधवार वर्ष 07 अंक 13 पृष्ठ 8 कीमत 5 रु.

Inside News

फ्यूल प्राइज में आ सकती है गिरावट नवंबर में 21 फीसदी तक सस्ता हुआ क्रूड Page 2

वीगन भोजन शैली के विविध स्वादों से प्रेरित - मैरियट इंटरनेशनल का 'मूड डाइट्स 2.0' Page 4

केंद्र सरकार ने कोरोना से उबार ली अर्थव्यवस्था Page 7

editoria!

तेल पर लगाम

तेल और गैस की ऊंची कीमतों से जूझते दुनिया के प्रमुख तेल उपभोक्ता देशों ने पूरे तालमेल के साथ अपने भंडार से तेल की आपूर्ति बढ़ाने का फैसला किया है। अपनी तरह की इस पहली और अनोखी पहल का मकसद अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों को नीचे लाना है। ध्यान रहे, पिछले करीब एक साल में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में 50 फीसदी से ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है। पिछले महीने यह तीन साल के शिखर 86 डॉलर प्रति बैरल को भी पार कर गया था। भारत और अमेरिका समेत तमाम तेल उपभोक्ता देश तेल निर्यातक देशों के समूह ओपेक (ऑर्गनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज) से बार-बार तेल उत्पादन में मांग के अनुरूप बढ़ोतरी लाने का आग्रह कर रहे हैं, लेकिन वह इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे में अमेरिका, चीन, भारत, जापान, साउथ कोरिया, ब्रिटेन जैसे देशों ने अपने भंडारों से तेल की आपूर्ति बढ़ाने का फैसला किया है। गौर करने की बात है कि कोरोना महामारी के उथल-पुथल भरे इस दौर में एनर्जी मार्केट को असाधारण उतार-चढ़ावों से गुजरना पड़ा। लॉकडाउन जैसे कदमों के प्रभाव में एक समय उत्पादन संबंधी गतिविधियां ठप पड़ने से तेल की मांग में अभूतपूर्व कमी आ गई थी। उसके बाद धीरे-धीरे हालात बदले। लेकिन अब जब मांग महामारी से पहले के स्तर पर पहुंच रही है, तेल सप्लाई उस अनुपात में नहीं बढ़ रही, जिससे न केवल इन देशों में पेट्रोल और गैस के भाव आसमान छू रहे हैं बल्कि आम लोगों को कई अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भारत में भी बेलगाम हो रही पेट्रोल की कीमतों को कुछ हद तक नियंत्रित करने के लिए एक्साइज ड्यूटी में कमी लानी पड़ी, जिससे सरकारी खजाने पर करीब 60,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा। हालांकि, यह बात भी सच है कि भारत में हाल के वर्षों में इस पर एक्साइज ड्यूटी में काफी बढ़ोतरी हुई थी। असल में, तेल की ऊंची कीमतें न केवल महंगाई बढ़ा रही हैं बल्कि इस वजह से इकॉनमिक रिकवरी में भी मुश्किल हो रही है। अपने रिजर्व से तेल निकाल कर ओपेक देशों को उपयुक्त संदेश देने का यह फैसला इसी मजबूरी से निकला है। हालांकि चाहे भारत के 3.8 करोड़ बैरल के भंडार में से 50 लाख बैरल निकालने की बात हो या अमेरिका के 60 करोड़ बैरल के भंडार में से 5 करोड़ बैरल निकालने की, यह मात्रा इतनी कम है कि इसका कोई और अर्थ नहीं लिया जा सकता। निश्चित रूप से यह एक सांकेतिक कदम है। अब देखने वाली बात यह है कि ओपेक देश इसे किस रूप में लेते हैं। उनकी अगली बैठक 2 दिसंबर को होनी है जिसमें वे जनवरी के लिए अपनी उत्पादन योजना को अंतिम रूप देंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि ओपेक तेल उपभोक्ता देशों के इस कदम को सही संदर्भों में लेते हुए इस पर पॉजिटिव ढंग से रिएक्ट करेगा।

क्रूड की कीमतों ने पकड़ी रफ्तार

एमसीएक्स पर दाम करीब 4% चढ़े

नई दिल्ली। एजेंसी

ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों की वजह से सोने चांदी की कीमतों में दबाव बना हुआ है। वहीं OPEC+ की बैठक से पहले क्रूड में तेजी देखने को मिल रही है। वहीं 3 और 4 दिसंबर को दो राज्यों में चक्रवाती तूफान का खतरा है। फर्टिलाइजर पर सब्सिडी बढ़ने की खबरों से फर्टिलाइजर शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। कच्चा तेल मंगलवार की गिरावट के बाद संभला है। ब्रेंट पर भाव में 2.25% से ज्यादा की तेजी आई है। ब्रेंट पर क्रूड ने 71.11 डॉलर का हाई लगाया है। WTI क्रूड में भी 2% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। MCX पर भी भाव करीब 4% चढ़ा है। MCX पर क्रूड ने 5,139 का हाई लगाया है।

दबाव में सोना-चांदी

COMEX पर सोने का भाव 7 हफ्ते के नीचे आया है। श्र्ें पर सोने के भाव 4 दिनों के

नीचे पहुंचा है। COMEX पर चांदी ऊपर लेकिन भाव 18 महीने के नीचे फिसला है। जुलाई 2020 को चांदी ने 26.74 डॉलर का स्तर छुआ था। श्र्ें पर भी चांदी का भाव 18 महीने के नीचे है। जुलाई 2020 को चांदी ने 67,560 का स्तर छुआ था। ळए ईं के बयान के बाद कीमतों पर दबाव बना हुआ है। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों से भी दबाव बना है।

फर्टिलाइजर पर बड़ा फैसला

सरकार फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ाने की तैयारी में है। 2021-22 के लिए सब्सिडी बढ़ाने की तैयारी में है। सरकार की 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा सब्सिडी देने की योजना है। बजट में तय रकम से करीब दोगुनी सब्सिडी संभव है। खाद की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए फैसला संभव है।

चढ़े फर्टिलाइजर के भाव

इंटरनेशनल मार्केट में फर्टिलाइजर की कीमतें चढ़ीं है। पिछले 1 साल कीमतों में करीब 200 फीसदी का उछाल आया है। कोयला, नेचुरल गैस की कीमतों में तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है। चीन, रूस ने फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा है। बता दें कि भारत सालाना मांग का 60% इंपोर्ट करता है। 60% में से 40% इंपोर्ट चीन से होता है । चीन में एक्सपोर्ट पर पाबंदी सप्लाई घटी है।

वित्त मंत्री का बड़ा बयान, कहा- क्रिप्टो पर जल्द लाएंगे बिल

नई दिल्ली। एजेंसी

राज्यसभा में क्रिप्टोकरेंसी पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि, 'यह एक 'जोखिम भरा' क्षेत्र है और पूर्ण नियामक ढांचे में नहीं है। क्रिप्टोकरेंसी के विज्ञापन पर रोक लगाने पर कोई फैसला नहीं लिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और बाजार नियामक (SEBI) के माध्यम से जागरूकता पैदा करने के लिए कदम उठाए गए हैं। सरकार जल्द ही एक विधेयक पेश करेगी।' सांसद सुशील कुमार द्वारा विज्ञापनों पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर, सीतारमण ने कहा कि 'क्रिप्टोकरेंसी के विज्ञापनों पर अंकुश लगाने के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है, लेकिन निवेशकों को सावधान किया गया है।'

टैक्स पर कही ये बात

क्रिप्टो ट्रेड पर एकत्र किए गए करों पर, सीतारमण ने कहा कि, 'क्रिप्टोकरेंसी पर एकत्र किए गए कर की राशि के बारे में तैयार जानकारी नहीं है।' इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने डिजिटल करेंसी में ट्रेडिंग को लेकर चेतावनी जारी की थी। दास ने कहा कि भारत में क्रिप्टोकरेंसी की औपचारिक शुरुआत से पहले चर्चा की जरूरत थी। उन्होंने यह भी कहा कि वर्चुअल करेंसी में लेनदेन का मूल्य बढ़ा है। करीब 80 फीसदी खातों में 2,000 रुपये से कम का बैलेंस है।

बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में मान्यता देने का कोई प्रस्ताव नहीं

सोमवार को वित्त मंत्री ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि बिटकॉइन को भारत की मुद्रा के रूप में मान्यता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा था कि सरकार बिटकॉइन लेनदेन पर डेटा एकत्र नहीं करती है। सरकार क्रिप्टोकरेंसी और रेगुलेशन ऑफ आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2021 को पेश करने वाली है।

नवंबर में जीएसटी कलेक्शन को नई ऊंचाई

लगातार दूसरे माह 1.30 लाख करोड़ के पार पहुंचा आंकड़ा

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

नवंबर महीने में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 1,31,526 करोड़ रुपये का हुआ। इस महीने का जीएसटी कलेक्शन पिछले महीने यानी अक्टूबर के संग्रह से ज्यादा है। इसमें सीजीएसटी 23,978 करोड़ रुपए, एसजीएसटी 31,127 करोड़ रुपए, आईजीएसटी 66,815 करोड़ रुपए और उपकर 9,606 करोड़ रुपए है। लगातार दूसरे महीने सकल जीएसटी संग्रह 1.30 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। नवंबर 2021 के महीने का राजस्व पिछले साल के इसी महीने में जीएसटी राजस्व से 25 फीसदी अधिक और 2019-20 से 27 फीसदी अधिक है। अक्टूबर, 2021 में जीएसटी कलेक्शन 1,30,127 करोड़ रुपये रहा। इसमें सीजीएसटी 23,861 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 30,421 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 67,361 करोड़ रुपये और उपकर (सेस) 8,484 करोड़ रुपये शामिल हैं। अक्टूबर के दौरान जीएसटी रेवेन्यू, जीएसटी लागू होने के बाद से दूसरा सबसे बड़ा मासिक संग्रह था।

उत्तरी अल्जीरिया की रिफाइनरी में आग लगने से 9 घायल

अल्जीयर्स। एजेंसी

उत्तरी अल्जीरिया में एक तेल रिफाइनरी में आग लगने से 9 लोग घायल हो गए। आधिकारिक एपीएस समाचार एजेंसी ने यह जानकारी दी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने एपीएस का हवाला देते हुए कहा कि आग मंगलवार सुबह सरकारी स्वामित्व वाले सोनात्राच समूह की स्किकाडा रिफाइनरी में लगी, लेकिन तुरंत बुझा दी गई। अल्जीरियाई ऊर्जा और खान मंत्री मोहम्मद अर्कब ने एपीएस के हवाले से कहा, इस दर्दनाक घटना में 9 लोग घायल हो गए, जो नियमित रखरखाव का काम कर रहे थे। अर्कब ने कहा, हालांकि, आग ने रिफाइनरी के उत्पादन को प्रभावित नहीं किया, रिफाइनरी ने अपना संचालन जारी रखा। मंत्री ने कहा कि सोनात्राच ने आग पर तुरंत काबू पाने के लिए सभी एहतियाती कदम उठाए हैं। राजधानी अल्जीयर्स से 500 किमी पूर्व में स्थित स्किकाडा रिफाइनरी, उत्तरी अफ्रीकी देश की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण रिफाइनरियों में से एक है।

फ्यूल प्राइज में आ सकती है गिरावट

नवंबर में २१ फीसदी तक सस्ता हुआ क्रूड

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत में गिरावट देखने को मिल सकती है। इसका कारण है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम में 21 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है। वास्तव में मार्च 2021 यानी 20 महीने के बाद किसी महीने में क्रूड ऑयल की कीमत में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। जिसकी वजह से डब्ल्यूटीआई और ब्रेंट क्रूड की कीमत अगस्त महीने के स्तर पर आ चुकी है। मंगलवार को क्रूड ऑयल के दाम में 6 फीसदी तक की गिरावट देखने को मिली थी। यह गिरावट मॉडर्ना के प्रमुख द्वारा ओमिक्रॉन कोरोनावायरस वैरिएंट के खिलाफ कोविड-19 वैक्सीन की एफिकेसी यानी प्रभावकारिता पर संदेह के बाद देखने को मिली।

क्यों आई गिरावट

ड्रगमेकर मॉडर्ना इंक के प्रमुख ने बताया कि कोविड-19 के टीके कोरोनवायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ उतने प्रभावी होने की संभावना नहीं है, जितना कि वे डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ हैं। वहीं दूसरी ओर वहीं दूसरी ओर कीमतों पर दबाव डालते हुए, फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने कहा कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक संभवतः अपनी अगली पॉलिसी बैठक में

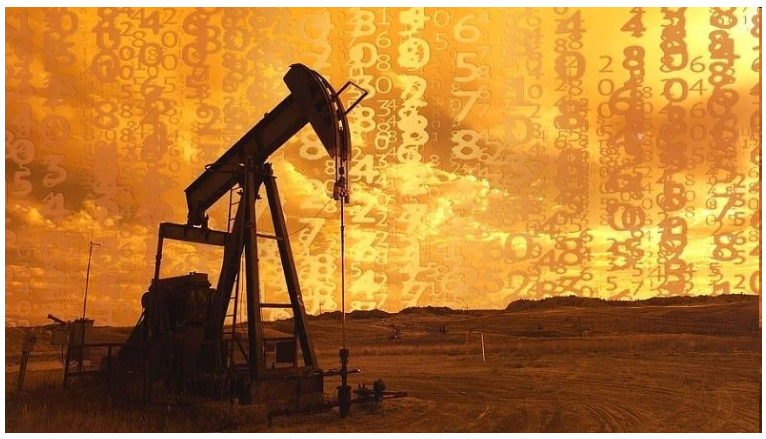

बड़े पैमाने पर बांड खरीद में कमी पर चर्चा करेगा, एक मजबूत अर्थव्यवस्था के बीच और उम्मीद है कि मुद्रास्फीति में वृद्धि अगले वर्ष के बीच में बनी रहेगी।

क्रूड ऑयल की कीमत में बड़ी गिरावट

इन बयानों के बाद ब्रेंट क्रूड वायदा 2.87 डॉलर, या 3.9 फीसदी गिरकर 70.57 प्रति बैरल पर आ गया था, जो अगस्त के बाद से सबसे कम 70.22 के निचले स्तर पर पहुंचा। वहीं यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड फ्यूचर्स 3.77 डॉलर यानी 5.4 फीसदी की गिरावट के साथ 66.18 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ। बेंचमार्क 64.43 डॉलर के सत्र के निचले स्तर तक गिर गया, जो अगस्त के बाद से सबसे कम है। वहीं दूसरी ओर बुधवार की सुबह डब्ल्यूटीआई 2.31 फीसदी यानी 1.53 डॉलर की तेजी के साथ 67.71 डॉलर पर कारोबार कर रही है। जबकि ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम करीब 4 डॉलर की गिरावट के साथ 70.57 डॉलर पर करोबार कर रहा है।

नवंबर के महीने में बड़ी गिरावट

आंकड़ों के अनुसार नवंबर महीने में ब्रेंट 16.4 फीसदी और डब्ल्यूटीआई में 20.8 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है। जोकि मार्च 2020 के बाद सबसे बड़ी मासिक गिरावट है। रिस्टैड एनर्जी के वरिष्ठ तेल बाजार विश्लेषक लुईस डिक्सन ने कहा कि तेल की मांग के लिए खतरा वास्तविक है। लॉकडाउन की एक और लहर के परिणामस्वरूप 2022 की पहली तिमाही में तेल की मांग में 3 मिलियन बीपीडी (प्रति दिन बैरल) की कमी हो सकती है।

भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं

वहीं दूसरी ओर क्रूड ऑयल की कीमत में बड़ी गिरावट के बाद भी भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। देश के चारों महानगरों में पेट्रोल और डीजल के दाम 4 हफ्तों के जस के तस बने हुए हैं। अगर बात भारत के वायदा बाजार की बात करें तो मंगलवार को क्रूड ऑयल की कीमत में 8.59 फीसदी यानी 459 रुपए प्रति? बैरल की गिरावट देखने को मिली है। जिसके बाद क्रूड ऑयल के दाम 4884 रुपए प्रति बैरल पर आ गए हैं।

जीएसटी काउंसिल ने दी अहम जानकारी

बताया कब तक पेट्रोल-डीज़ल जीएसटी दायरे में आएगा

नई दिल्ली। एजेंसी

अगर जीएसटी दायरे में पेट्रोल-डीज़ल आ जाता है तो एक झटके में 20-25 रुपये प्रति लीटर तक इनकी कीमतें कम हो जाएंगी। हालांकि, इस पर राज्य और केंद्र सरकार में सहमति नहीं बन पा रही है। क्योंकि, राज्य सरकारों की कमाई का मुख्य जरिया पेट्रोल-डीज़ल पर लगने वाला टैक्स है। अब खबर आ रही है कि एक जीएसटी काउंसिल ने एक बार फिर से इस मामले को टाल दिया है। काउंसिल का कहना है कि कोरोना अभी तक खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए आने वाले दिनों में कमाई घटने की चिंता बनी हुई है।आपको बता दें कि बुधवार को दिल्ली सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए पेट्रोल के दाम को सस्ता कर दिया है। पेट्रोल पर वैट घटाने का फैसला लिया है। इस फैसले के बाद दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल 8 रुपए तक सस्ता हो जाएगा। दिल्ली सरकार के इस ऐलान के बाद दिल्ली-एनसीआर में सबसे सस्ता पेट्रोल दिल्ली में मिलेगा। इस ऐलान के पहले तक दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल के दाम 104.01 रुपए थे। जो 8 रुपए प्रति लीटर घटने के बाद करीब 96.01 रुपए लीटर पर आ गए हैं।

क्या केंद्र सरकार को भी पेट्रोल के जीएसटी में आने से नुकसान होगा? पिछले कुछ दिनों पहले आई SBI रिपोर्ट के मुताबिक, जीएसटी के दायरे में आने के बाद पेट्रोल करीब 20-25 रुपये और डीजल करीब 20 रुपये तक सस्ता हो जाएगा। ऐसा होते ही सबसे पहले राज्यों को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। अभी तक डीजल-पेट्रोल इसी वजह से जीएसटी के दायरे में नहीं आ पाया है, क्योंकि कोई भी राज्य अपना नुकसान नहीं कराना चाहता है। राज्यों की अधिकतर आय डीजल-पेट्रोल पर लगाए जाने वाले टैक्स से ही होती है, इसलिए राज्य पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का विरोध कर रहे हैं. इससे केंद्र सरकार को भी करीब 1 लाख करोड़ रुपये का नुकसान होगा, जो जीडीपी के 0.4 फीसदी के बराबर है। 2019 में पेट्रोल पर टोटल एक्साइज ड्यूटी 19.98 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 15.83 रुपये प्रति लीटर था। सरकार ने पिछले साल दो बार एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया, जिसके चलते पेट्रोल पर यह बढ़कर 32.98 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 31.83 रुपये प्रति लीटर हो गया। इस साल के बजट में पेट्रोल पर शुल्क को घटाकर 32.90 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 31.80 रुपये प्रति लीटर किया गया था। इस महीने पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गईं, जिसके चलते पेट्रोल पर 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई।

रुपया शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 29 पैसे बढ़कर 74.84 पर पहुंचा

मुंबई। एजेंसी

घरेलू शेयर बाजार के सकारात्मक रुख और विदेशी बाजारों में अमेरिकी मुद्रा के कमजोर होने से निवेशकों की धारणा मजबूत होने के मद्देनजर रुपया बुधवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 29 पैसे बढ़कर 74.84 पर पहुंच गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय में, रुपया 74.96 पर खुला, और शुरुआती कारोबार में 29 पैसे की वृद्धि दर्ज करते हुए अमेरिकी डॉलर के मुकाबले बढ़कर 74.84 पर पहुंच गया। अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के नए स्वरूप के असर से निवेशकों की चिंता बढ़ने के कारण अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में मंगलवार को चौथे दिन भी गिरावट हुई, जो कि 6 पैसे गिरकर 75.13 पर आ गया था। इस बीच, डॉलर सूचकांक 0.06 प्रतिशत फिसलकर 95.93 पर आ गया। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वायदा 3.91 प्रतिशत की गिरावट के साथ 70.57 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।

ओमिक्रॉन एलर्ट के बाद इंटरनेशनल बुकिंग्स पर दिख रहा असर

ग्लोबल टूरिज्म को 2 ट्रिलयल डॉलर का नुकसान संभव

एजेंसी

कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन से ट्रेवल और टूरिज्म सेक्टर एक बार फिर सहम गया है। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक बुकिंग्स में गिरावट देखी जा रही है। टूरिस्ट पहले की गई बुकिंग्स को रिशेड्यूल और कैंसिल करने को लेकर भी पूछताछ कर रहे हैं। कोरोना की पहली और दूसरी लहर की मार से उबरने में जुटे टूर एंड ट्रैवल सेक्टर फिर चिंता में पड़ गया है। मुफ्त टूरिस्ट वीज़ा और इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बहाली से हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में रिकवरी की उम्मीदें भी जगी थीं लेकिन नए वैरिएंट ओमिक्रॉन की आहट उम्मीदों पर पानी फेर सकता है। वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गनाईजेशन के एलर्ट के बाद टूरिस्ट असमंजस में है। जिसका सीधा असर बुकिंग्स पर पड़ रहा है। यूनाईटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म आर्गनाईजेशन (UNWTO) की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल टूरिज्म को इस साल भी करीब 2 ट्रिलयल डॉलर का नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जुलाई से लेकर सितंबर तक टूरिस्ट अराइवल में 58इ की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है लेकिन ये ग्रोथ अभी भी प्री कोविड लेवल से कम है। साल 2019 में इसी दौरान 64% का ग्रोथ दर्ज की गई थी । देश के होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के मुताबिक इंटरनेशनल बुकिंग्स प्रभावित हो रही है लेकिन डोमेस्टिक बुकिंग्स पर फिलहाल कोई असर नहीं है। ओमिक्रॉन वायरस से प्रभावित देशों के अलावा दुनियां के बाकी देश भी अपने ट्रैवल एडवाजरी और गाईडलाईन्स में लगातार बदलाव कर रहे हैं। ऐसे में उन लोगों को काफी परेशानी हो रही है जो इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं। ज्यादातर टूरिस्ट ट्रैवल प्लान को कटशॉर्ट कर रहे हैं और जो लोग प्लान बना चुके थे। वो भी हालात को देखते हुए अपने ट्रेवल प्लान को होल्ड करने या ठंडे बस्ते में डालने के लिए मजबूर हो रहे हैं।

ब्रिटेन में 'ओमिक्रॉन' के 22 मामले मिलने से हड़कंप, जापान में बूस्टर डोज लगाने का फैसला

एजेंसी। कोरोना का नया वैरिएंट ओमिक्रॉन से खतरा बढ़ता ही जा रहा है। ताजा मामला है ब्रिटेन का जहां ओमिक्रॉन वैरिएंट के 22 मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं जापान ने इसके खतरे को देखते हुए बूस्टर डोज लगाने का फैसला किया है। दुनिया के कई देशों में जहां ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है वहीं भारत में भी सतर्कता बरती जा रही है। एयरपोर्ट से लेकर बस अड्डे तक जांच बढ़ा दी गई है। कई राज्यों ने स्वतंत्र तौर पर दिशानिर्देश भी जारी कर दिए हैं। इसी कड़ी में अब महाराष्ट्र ने भी कोरोना नियमों को सख्त करते हुए जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना की आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य कर दिया है। दुनिया के कई देशों में जहां ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है वहीं भारत में भी सतर्कता बरती जा रही है। एयरपोर्ट से लेकर बस अड्डे तक जांच बढ़ा दी गई है। कई राज्यों ने स्वतंत्र तौर पर दिशानिर्देश भी जारी कर दिए हैं। इसी कड़ी में अब महाराष्ट्र ने भी कोरोना नियमों को सख्त करते हुए जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना की आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य कर दिया है।

वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट ने एमएसएमई को प्रशिक्षण और सहयोग के लिए मप्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर

संदीप सखलेचा

भोपाल। वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट ने आज मध्य प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग (एमएसएमई) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की। इसके तहत एक दूसरे के साथ नजदीकी सहयोग से काम किया जाएगा और राज्य में एमएसएमई की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ईकोसिस्टम तैयार किया जाएगा। इस भागीदारी के तहत, वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट एमएसएमई को उनके व्यवसायों को डिजिटाइज़ बनाने में मदद करेंगे और उन्हें ऑनलाइन रिटेल के ज़रिए पूरे भारत में उत्पाद बेचने में सक्षम बनाएंगे। एमएसएमई के पास निर्यात की क्षमता विकसित करके वॉलमार्ट की ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनने का मौका भी होगा। स्वस्ति के साथ मिलकर वॉलमार्ट वृद्धि सप्लायर डेवलपमेंट प्रोग्राम (वॉलमार्ट वृद्धि) व्यापक लर्निंग प्लेटफार्म मुहैया करवाता है, जिसमें विकास के अवसर, मुफ्त प्रशिक्षण और उद्यमियों तथा छोटे व्यवसायों को विशेषज्ञों से सहायता देना शामिल है। इस कार्यक्रम के तहत राज्य में लघु और मध्यम व्यवसायों के विकास को आगे बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग सेमिनार और वर्कशॉप्स भी आयोजित किए जाएंगे। वॉलमार्ट वृद्धि को वर्ष 2019 में शुरू किया गया था। वॉलमार्ट वृद्धि का लक्ष्य 50,000 भारतीय एमएसएमई को उन बिजनेस स्किल्स में प्रशिक्षित करना है, जिनकी वॉलमार्ट के सप्लायर बनने, फ्लिपकार्ट पर विक्रेता बनने और दूसरे स्थानीय व ग्लोबल मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म पर सफल होने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। कई राज्यों में हजारों वृद्धि एमएसएमई ग्रेजुएट्स को उनकी घरेलू क्षमताओं को बढ़ाने और ग्लोबल सप्लाई चेन में भाग लेने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्हें सस्टेनेबल बिजनेस बनाने, रोजगार पैदा करने और निर्यात बढ़ाने में मदद की जा रही है। पानीपत और आगरा में वृद्धि ई-इंस्टीट्यूट्स के साथ-साथ कई दूसरी जगहों पर मौजूद यह कार्यक्रम व्यक्तिगत फीडबैक और वन-टू-वन एडवाइज़री सेशन के साथ-साथ ऑनलाइन मॉड्यूल के ज़रिए डिजिटल तरीके से सीखने का बेहतरीन अनुभव देता है।

मध्य प्रदेश के एमएसएमई, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, माननीय श्री ओम प्रकाश सखलेचा ने कहा, 'मध्य प्रदेश सरकार ने एमएसएमई के अनुकूल ईकोसिस्टम बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं क्योंकि 'आत्मनिर्भर भारत' में इनकी अहम भूमिका है। अब यह ज़रूरी हो गया है कि छोटे व्यवसाय अपना विस्तार करें और अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए आधुनिक टैक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। हमें वॉलमार्ट वृद्धि जैसे कार्यक्रम के साथ भागीदारी करके बहुत खुशी हो रही है और हम इस कार्यक्रम के ज़रिए एमएसएमई को सफल बनाने में अपना सहयोग और मार्गदर्शन देते रहेंगे।'

वॉलमार्ट में इंटरनेशनल पार्टनरशिप सर्विसेज की वाइस प्रेसिडेंट, निधि मुंजाल ने कहा, 'हम मध्य प्रदेश सरकार के साथ भागीदारी करने और मजबूत एमएसएमई ईकोसिस्टम तैयार करने के उनके प्रयासों में सहयोग करके बहुत उत्साहित हैं। हम स्थानीय प्रशिक्षण और सहयोग के ज़रिए एमएसएमई को भारत और विश्व के बाज़ारों तक ऑनलाइन और ऑफलाइन पहुंच बनाने का अवसर देंगे। हम वर्ष 2027 तक भारत से अपने निर्यात को तीन गुना बढ़ाकर 10 अरब डॉलर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम छोटे व्यवसायों को अपना समर्थन देते रहेंगे, ताकि वे भारत और दुनिया के बाजारों में अपना विकास कर सकें।'

फ्लिपकार्ट के सीनियर डायरेक्टर और हेड-मार्केटप्लेस जगजीत हरोडे ने कहा, 'हमें भोपाल, इंदौर और कई दूसरे शहरों के एमएसएमई से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। वे अपने व्यापार कोऑनलाइन ले जाना चाहते हैं। वर्तमान में फ्लिपकार्ट मार्केटप्लेस करीब 4 लाख विक्रेताओं को डिजिटल कॉमर्स में सहयोग देती है। वॉलमार्ट वृद्धि और फ्लिपकार्ट समर्थ जैसे कार्यक्रमों के ज़रिए हम मध्य प्रदेश के एमएसएमई, कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम उन्हें ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस के ज़रिए पूरे भारत तक पहुंच बनाने के लिए ज़रूरी इकोसिस्टम सपोर्ट देना जारी रखेंगे।'

वॉलमार्ट वृद्धि कार्यक्रम के तहत, वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट ने हरियाणा और तमिलनाडु सहित देश के कई राज्यों के साथ भागीदारी की है। मध्य प्रदेश सरकार के साथ इस नई भागीदारी के तहत हम एमएसएमई को भारत और दुनिया भर के ऑनलाइन व ऑफलाइन बाजारों तक संभावित पहुंच प्रदान करने के साथ-साथ मुफ्त स्थानीय प्रशिक्षण और सहायता देकर उन्हें आगे बढ़ने में मदद करेंगे।

वीगन भोजन शैली के विविध स्वादों से प्रेरित - मैरियट इंटरनेशनल का 'मूड डाइट्स 2.0'

एक स्पर्धा के माध्यम से 15 शहरों से क्राउड सोर्स किए जाएंगे व्यंजन

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

अपने सभी होटल और रेस्टॉरेंट में कुछ नायब और शानदार व्यंजन पेश करने के लिए प्रतिबद्ध, मैरियट इंटरनेशनल ने इस वर्ष की शुरुआत में 'मूड डाइट्स' मेन्यू जारी किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था मेहमानों की पोषण की ज़रूरतों को पूरा करना और साथ ही अलग-अलग मूड और स्वभाव को ध्यान में रखते हुए उसके अनुरूप अलग-अलग स्वाद के व्यंजन उन्हें परोसना। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैरियट इंटरनेशनल ला रहा है 'मूड डाइट्स 2.0', जिसमें सभी व्यंजनों को नेचरल और प्लांट-बेस्ड पदार्थों से तैयार कर वीगन बनाया जाएगा। नया मूड-डाइट 2.0 का मेन्यू 15 शहरों में एक प्रतियोगिता आयोजित कर, जनता के साथ मिल कर बनाया जायेगा। इसमें भाग ले रहे प्रतिभागियों को एक आसान, बिना झंझट वाले व्यंजन की रेसीपी भेजनी है जो की वीगन आधारित हो, और हमारे मास्टर शेफ द्वारा चुने गए 10 ऑर्गेनिक पदार्थों में से एक या एक से ज्यादा पदार्थों को इस्तेमाल कर बनाई गई हो। तीन सबसे बढ़िया व्यंजन 'मूड डाइट्स 2.0' के नए मेन्यू में शामिल किये जाएंगे जो की इस वर्ष के अंत तक जारी होगा। इस पहल को लेकर खुशनुमा कपाड़िया, सीनियर एरिया डायरेक्टर ऑफ़ मार्केटिंग - साउथ एशिया, मैरियट इंटरनेशनल ने कहा, 'मूड डाइट्स का हमारा पहला भाग - हमारे डिलीवरी प्लेटफार्म - मैरियट बॉनवॉय को व्हील्स के तहत जब हमने शुरू किया था तो उसे भारत के काफी सारे होटलों में बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला था। इस क्राउड सोर्स किये जाने वाले मेन्यू को लेकर हिमांशु तनेजा, क्युलिनरी डायरेक्टर, साउथ एशिया, मैरियट इंटरनेशनल ने कहा, 'खाने में इस्तेमाल होने वाली प्रत्येक सामग्री का एक अपना स्वाद होता है, और ऐसी कितनी

ही सामग्रियां है जिनका स्वाद हमे मालूम ही नहीं है। इस पहल के साथ ही, हम पूरे समाज के साथ जुड़ना चाहते है और उन्हें उनके स्थानीय शैली में कुछ ख़ास नए व्यंजन बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। साथ ही, शोध से यह भी पता चलता है कि एक सस्टेनेबल आहार मूड और उत्पादकता के स्तर में सुधार करता है, जिसके कारण वीगन व्यंजन मूड डाइट मेन्यू के लिए एक श्रेष्ठ विकल्प है।' 'मूड डाइट्स 2.0' कुल 21 मैरियट इंटरनल होटल में जारी किया जाएगा।

News यू केन USE

सरकार ने एगर तेल, एगरवुड चिप्स, पाउडर के निर्यात पर पाबंदी लगायी

नयी दिल्ली। एजेंसी

सरकार ने सोमवार को एगरवुड चिप्स, पाउडर और एगर तेल के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से पाबंदी लगा दी। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा कि एगरवुड चिप्स और पाउडर के लिए सालाना 25,000 किलो का निर्यात कोटा तथा एगर तेल के लिए 1,500 किलो का निर्यात कोटा अधिसूचित किया गया है। इसके अनुसार, ''एगर तेल और एगरवुड चिप्स तथा पाउडर की निर्यात नीति को संशोधित कर इसे तत्काल प्रभाव से मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में डाला गया है।'' एगरवुड का उपयोग अगरबत्ती और धूप बनाने में किया जाता है। यह मुख्य रूप से त्रिपुरा और असम में होता है। एक अलग अधिसूचना में, डीजीएफटी ने कहा कि यूनिवर्सल क्रॉप प्रोटेक्शन को एनपी / एनपीके (नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम) उर्वरक के निर्माताओं / इकाइयों की सूची में शामिल किया गया है। ये कुछ शर्तों के तहत अपने उत्पादन का स्वतंत्र रूप से निर्यात कर सकते हैं। सूची में अब 19 कंपनियां हो गई हैं।

व्हाट्सएप को भुगतान उपयोगकर्ता आधार दोगुना करने के लिए एनपीसीआई की मंजूरी

मुंबई। एजेंसी

फेसबुक के स्वामित्व वाली मैसेजिंग सेवा व्हाट्सएप को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने भुगतान सेवा के लिए अपने उपयोगकर्ता आधार को दोगुना कर चार करोड़ करने की मंजूरी दे दी है। भारत में व्हाट्सएप का कुल उपयोगकर्ता आधार 40 करोड़ है और इस मंजूरी के साथ उसे गूगल पे और फोन पे जैसी मजबूत प्रतिद्वंद्वियों के साथ बेहतर प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी। अमेरिकी कंपनी की लंबे समय से भुगतान के अवसरों पर नजर थी, लेकिन डेटा स्थानीयकरण संबंधी जरूरतों के कारण उसकी सेवा की शुरूआत में देरी हुई। यह घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब नियामक वित्तीय क्षेत्र में बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों की भूमिका को लेकर खुलकर चिंता जता रहे हैं। एनपीसीआई की वेबसाइट पर तीसरे पक्ष के ऐप की सूची से साफ हो जाता है कि व्हाट्सएप को उपभोक्ता आधार बढ़ाकर चार करोड़ करने की मंजूरी दे दी गयी है।

ओएनडीसी में 9.5 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ प्रवर्तक बनेगा पीएनबी

नयी दिल्ली।आईपीटी नेटवर्क

सार्वजनिक क्षेत्र का पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) प्रस्तावित कंपनी 'ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स' (ओएनडीसी) में नौ प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी के साथ प्रवर्तक के तौर पर जुड़ने जा रहा है। पीएनबी ने सोमवार को शेयर बाजार को दी गई सूचना में कहा कि डिजिटल कॉमर्स के लिए एक मुक्त नेटवर्क के विकास के इरादे से ओएनडीसी का गठन किया जा रहा है। बैंक ने कहा कि ओएनडीसी की इक्विटी पूंजी में उसकी हिस्सेदारी 9.5 प्रतिशत होगी। पीएनबी ने कहा, ''यह निवेश एक या दो किस्तों में किया जाएगा। इस निवेश के लिए समयसीमा को भी अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।'' बैंक के मुताबिक, नई कंपनी में उसकी शेयरधारिता दस प्रतिशत से कम होने की वजह से उसे नियामकीय मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। भारत में ई-कॉमर्स कारोबार का एक मुक्त डिजिटल नेटवर्क खड़ा करने के लिए ओएनडीसी का गठन किया जा रहा है। इस तरह के मंच पर कोई विक्रेता पंजीकरण के बगैर भी अपने उत्पाद बेच सकता है।

25 साल बाद ईपीएफओ पेंशन में सुधार को तदर्थ कमेटी

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

25 साल बाद ईपीएफओ पेंशन स्कीम में सुधार की पहल हुई है। केन्द्रीय श्रम मंत्री के निर्देश पर पहली बार पेंशन सुधार के लिए तदर्थ कमेटी गठित की गई है जिसे 3 महीने में अपनी रिपोर्ट ईपीएफओ की केन्द्रीय न्यासी बोर्ड में रखनी है। कमेटी को तत्काल पेंशन सुधार के लिए काम शुरू करने का प्रस्ताव भी कर दिया गया है। ईपीएफओ की न्यूनतम पेंशन एक हजार और अधिकतम 7.5 हजार तय है लेकिन सालों से सीबीटी सदस्य और पेंशनर्स मांग करते रहे हैं कि महंगाई के दौर में पेंशन वृद्धि के साथ सुधार किए जाए। उसी कड़ी में सीबीटी

चेयरमैन केन्द्रीय श्रम मंत्री के निर्देश पर पेंशन सुधार के लिए 8 सदस्यीय तदर्थ कमेटी बनाई है। ईपीएफओ (दिल्ली मुख्यालय) की केन्द्रीय अपर भविष्यनिधि आयुक्त उदिता चौधरी ने तदर्थ कमेटी का आदेश जारी किया है। कमेटी में श्रम मंत्रालय के सचिव को चेयरमैन बनाया गया है। केन्द्र सरकार के अधिकारियों के साथ सीबीटी में कर्मचारियों की ओर से सदस्य हरभज सिंह सिद्धू, प्रभाकर जे बंस्योर, नियोक्ता की ओर से अतुल सोबती और आशीष विग को भी सदस्य बनाया गया है। कमेटी की सिफारिशों की रिपोर्ट को तीन महीने के बाद होने वाली पहली सीबीटी बैठक में रखने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। कमेटी के सदस्य हरभजन सिंह ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा प्राथमिकता पर रहेगी। सालों पुरानी मांग पर सीबीटी चेयरमैन ने पहल तो कर दी है। यह अच्छे संकेत हैं। कमेटी 3 महीनों में हर हाल में रिपोर्ट देगी। 1995 के बाद पेंशन सुधार पर कम से कम कदम तो बढ़ाए गए हैं।

देश के घरों में हर रोज कितने LPG सिलेंडर की होती है खपत, सरकार ने संसद में बताया

नई दिल्ली। देश में हर रोज 14.2 किलोग्राम वाले 47.4 लाख घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों की खपत होती है। यह जानकारी पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने राज्यसभा को एक लिखित उत्तर में दी। उन्होंने सदन को बताया कि अप्रैल-सितंबर 2021 के दौरान तेल मार्केटिंग कंपनियों ने देश में पैक्ड डॉमेस्टिक और पैक्ड ऊ्र्ंथ्झ्उ की क्रमशः 12308 ऊश्ऊ और 995 ऊश्ऊ मात्रा की बिक्री की। इसका अर्थ हुआ कि उन्होंने रोज 14.2 ड्ड के 47.4 लाख और 19 ड्ड के 2.9 लाख सिलेंडरों की बिक्री की।

उन्होंने बताया कि घरेलू और गैर-घरेलू एलपीजी सिलेंडरों से राजस्व महीने दर महीने बदलता रहता है। इसकी वजह है कि खुदरा बिक्री मूल्य ध्श्णे, अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में उत्पाद की कीमतों और मुद्राओं की विनिमय दर के आधार पर अधिसूचित किए जाते हैं। हालांकि, सरकार घरेलू एलपीजी पर 5ड्ड और गैर-घरेलू एलपीजी पर 18ड्ड जीएसटी लगाती है।

सब्सिडी पर क्या बोले

मंत्री ने कहा कि घरेलू एलपीजी पर सब्सिडी हर बाजार में अलग-अलग होती है और गैर-सब्सिडी मूल्य पर एलपीजी रीफिल की खरीद पर लागू सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रान्सफर कर दी जाती है। सब्सिडी का बोझ सरकार वहन करती है।

33 प्रतिशत कुओं के जल स्तर में शून्य से दो मीटर तक की गिरावट दर्ज की गयी : केंद्र

नयी दिल्ली। एजेंसी

केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि निगरानी किए जाने वाले 33 प्रतिशत कुओं में भूजल स्तर में शून्य से दो मीटर तक की गिरावट दर्ज की गयी है। इसके साथ ही दिल्ली, चेन्नई, इलाहाबाद, कानपुर और लखनऊ जैसे शहरों के कुछ हिस्सों में चार मीटर से अधिक की गिरावट देखी गयी है। जल शक्ति राज्य मंत्री बिश्वेश्वर टुडू ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) निगरानी कुओं के एक नेटवर्क के जरिए महानगरों सहित देशभर में क्षेत्रीय स्तर पर भूजल स्तर की समय-समय पर निगरानी कर रहा है। उन्होंने कहा कि 'पर जल स्तर में गिरावट का दीर्घावधि आधार पर आकलन करने के लिए, नवंबर 2020 के दौरान सीजीडब्ल्यूबी द्वारा एकत्र किए गए जल स्तर के आंकड़ों की तुलना दशकीय औसत (2010-2019) से की गयी है।' मंत्री ने आगे कहा कि जल स्तर के आंकड़ों के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि निगरानी वाले करीब 33 प्रतिशत कुओं में भूजल स्तर में शून्य से दो मीटर तक की गिरावट दर्ज की गई है।

मेडिकल उपकरणों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चार विशेष पार्क स्थापित होंगे

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को कहा कि 'आत्मनिर्भर भारत योजना' के तहत देश में मेडिकल उपकरणों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दी है और चार विशेष पार्क स्थापित करने की योजना है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने चार राज्यों में मेडिकल उपकरण पार्क लगाने की मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश व तमिलनाडु शामिल हैं। इनके निर्माण के लिए सरकार की ओर से 100-100 करोड़ रुपये राज्य को दिए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि लोगों को मेडिकल सुविधाएं बढ़ने से उपकरणों की मांग में भी वृद्धि हुयी है। उन्होंने कहा कि दवाइयों के मामले में हम पहले से ही 'फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड' हैं और अमेरिका सहित पूरी दुनिया को भारत से दवाइयां भेजी जाती हैं। लेकिन मेडिकल उपकरणों के मामले में हमारी स्थिति ऐसी नहीं हैं और हम इसे बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। मांडविया ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न पूरक सवालों का जवाब देते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमने जोर दिया है कि सभी पार्क में एक ही सुविधा हो और उसका लाभ सभी को हो तो वह सस्ता भी हो जाता है।

आखिर क्यों पुलिसवालों को लोन नहीं देते हैं बैंक वित्तममंत्री ने राज्यसभा में दिया जवाब

नई दिल्ली। एजेंसी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि केंद्र ने बैंकों को पुलिस कर्मियों जैसे 'संवेदनशील ग्राहकों' को ऋण नहीं देने के लिए कोई विशेष निर्देश नहीं जारी किया है। वित्त मंत्री ने उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि बैंकों को कुछ श्रेणी के ग्राहकों को ऋण नहीं देने का निर्देश देने की कोई 'आधिकारिक नीति' नहीं है। उन्होंने कहा, 'बैंक केवाईसी और अन्य रेटिंग के आधार पर आकलन करते हैं। मैं नहीं समझती कि बैंकों को ऐसा कोई विशेष निर्देश दिया गया है कि कृपया इन लोगों को ऋण नहीं दें।'' उन्होंने कहा कि बैंक अपने उपलब्ध केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) के आधार पर अपने विवेक से फैसला करते हैं। वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने कहा कि बैंकों को पुलिस और नेताओं को ऋण देने में 'समस्याएं' हैं। उन्होंने कहा कि बैंक ऐसे ग्राहकों को कर्ज देने से पहले उनका 'ट्रैक रिकॉर्ड' देखते हैं। वे राजनीति से जुड़े लोगों (पीईपी) को बैंकों द्वारा कथित तौर पर ऋण नहीं देने के बारे पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। कराड ने कहा कि आवास ऋण मुख्यतः बैंकों तथा आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के रूप में पंजीकृत कुछ गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) के द्वारा दिए जाते हैं और इन संस्थाओं को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विनियमित किया जाता है।

केंद्र सरकार ने कोरोना से उबार ली अर्थव्यवस्था

पॉजिटिव संकेतों के बीच ये आंकड़े चिंताजनक

नई दिल्ली। एजेंसी

कोरोना के ओमीक्रॉन वैरिएंट के खतरे के बीच राहत की खबर है। यह खबर इकोनॉमी के मोर्चे पर आई है। पिछले दो साल से लॉकडाउन, कोरोना की दूसरी लहर से हिचकोले खा रही भारतीय इकोनॉमी कोरोना पूर्व की स्थिति में आ गई है। मंगलवार को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्या?वयन मंत्रालय द्वारा जारी जीडीपी आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था एक बार फिर 35 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गई है। जो कि कोरोना की दस्तक से पहले की स्थिति थी। ऐसे में यही सवाल उठता है कि क्या मोदी सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कोरोना के कहर से उबार लिया है।

क्या कहते हैं आंकड़े

वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही के आंकड़े के अनुसार उअ्र 35,73,451 करोड़ रुपये पर पहुंच गई है। जो कि कोरोना की दस्तक से पहले 2019-20 की दूसरी तिमाही के स्तर से थोड़ा ज्यादा है। उस दौरान उअ्र 35,61,530 करोड़ रुपये थी। जाहिर ये आंकड़े सुखद हैं। क्योंकि कोरोना की दस्तक के बाद लॉकडाउन लगने पर 2020-21 की पहली तिमाही में उअ्र निगेटिव स्तर में पहुंच गई थी और वह करीब 9 लाख करोड़ रुपये घटकर 26.95 लाख करोड़ पर आ गई थी। इस दौरान उअ्र में 24.4 फीसदी की गिरावट आई थी। जो कि लॉकडाउन हटने के बाद सुधरकर चालू वित्त वर्ष पहली तिमाही में 32.31 लाख करोड़ रुपये पहुंची थी। अहम बात यह है कि दूसरी तिमाही में मिली 8.4 फीसदी की ग्रोथ आरबीआई के अनुमान से भी ज्यादा है। आरबीआई का इस दौरान ग्रोथ 7.9 फीसदी रहने का अनुमान था।

इकोनॉमी में आए सुधार पर क्रिसिल के मुख्य अर्थशास्त्री डी.के.जोशी कहते हैं 'अर्थव्यवस्था में सुधार उम्मीद के अनुसार ही है। सरकार के बड़े पैमाने पर निवेश का असर दिख रहा है। हालांकि निजी क्षेत्र के खर्च में अभी भी अहम रिकवरी होना बाकी है।'

कृषि क्षेत्र का कमाल जारी

इकोनॉमी को पटरी पर लाने में सबसे बड़ा योगदान कृषि क्षेत्र का रहा है। पिछले दो साल से जब सभी सेक्टर निगेटिव ग्रोथ पर थे तो अकेले कृषि क्षेत्र ने अर्थव्यवस्था की नींव बचा कर रखी थी। 2020-21 की पहली और दूसरी तिमाही में कृषि क्षेत्र 3.5 और 3.0 फीसदी जबकि 2021-22 की पहली और दूसरी तिमाही में 4.5 फीसदी पर ग्रोथ बनी रही। इसके अलावा पिछली दो तिमाही में माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने रिकवरी की है और इकोनॉमी को पटरी पर लाने में अहम भूमिका निभाई है।

अच्छी खबर के बावजूद ये आंकड़े चिंताजनक

इसमें कोई दो राय नहीं है कि इकोनॉमी के मोर्चे पर गुड न्यूज है। लेकिन अभी भी कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो चिंताजनक हैं। इसका डी.के.जोशी ने भी इशारा किया है। उन्होंने कहा है कि निजी क्षेत्र के तरफ से खर्च में बढ़ोतरी होना बाकी है। निजी क्षेत्र का खर्च 2019-20 में पहली और दूसरी तिमाही के दौरान 20.19 लाख करोड़ के करीब था। जो अभी भी 19.48 लाख करोड़ रुपये बना हुआ है। यानी अभी कोरोना से पहले की स्थिति नहीं आई है। इसके अलावा अभी निजी वाहनों की बिक्री में सुधार नहीं दिखा है। वह दूसरी तिमाही में -10.4 फीसदी पर है। इसी तरह जीवीए के आधार पर देखा जाय तो कंस्ट्रक्शन और सर्विस सेक्टर में रिकवरी के बावजूद अभी वह 2019-20 के स्तर पर नहीं पहुंचे हैं। होटल इंडस्ट्री,ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन आदि अभी 10 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर हैं। जबकि कोरोना पूर्व यह 13 करोड़ रुपये के करीब था।

मोमेंटम बने रहना जरूर

उद्योग जगत के संगठन फिक्की के प्रेसिडेंट उदय शंकर का कहना है कि ग्रोथ रेट उम्मीद के अनुसार है। आज हम ऐसे समय में खड़े हैं, जो टर्निंग प्वाइंट साबित हो सकता है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि ग्रोथ का मौजूदा मोमेंटम आगे भी बना रहे। हमें उम्मीद है कि आरबीआई अगले हफ्ते अपनी मौद्रिक नीति में जमीनी स्थिति को देखते हुए फैसला लेगा। साफ है कि इकोनॉमी बेहतर स्थिति में आ गई है। ऐसे में अगर सरकार के तरफ से मोमेंटम मिला और निजी क्षेत्र का भरोसा लौटा तो वह नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकती है।

ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के करीब 10 करोड़ श्रमिकों ने पंजीकरण कराया

नयी दिल्ली। एजेंसी

श्रम मंत्रालय ने कहा है कि ई-श्रम पोर्टल पर अब तक असंगठित क्षेत्र के करीब 10 करोड़ श्रमिकों ने पंजीकरण कराया है। ई-श्रम पोर्टल सरकार की अनौपचारिक कार्यबल का राष्ट्रीय डाटाबेस बनाने की एक पहल है। सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डाटाबेस बनाने की खातिर इस साल अगस्त में ई-श्रम पोर्टल शुरू किया गया था।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'केंद्रीय मुख्य श्रम आयुक्त (सीएलसी) ने कहा कि सीएलसी क्षेत्र के अधिकारियों के 100 दिनों में संबंधित प्रयासों के कारण, ई-श्रम पोर्टल पर करीब 10 करोड़ श्रमिकों का पंजीकरण किया गया है। सभी अधिकारियों से प्रयास जारी रखने का अनुरोध किया गया है ताकि ऐसा कोई श्रमिक ना बचे जिसका पंजीकरण न किया गया हो।' बयान के अनुसार, 29 नवंबर, 2021 तक पोर्टल पर करीब 9.7 करोड़ (9,69,82,091) श्रमिकों का पंजीकरण हो चुका है, जिसमें एक दिन पहले से लगभग 15 लाख श्रमिकों (14,95,993) की वृद्धि हुई है।' ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या में साप्ताहिक वृद्धि, (कम से कम पिछले नौ सप्ताह से) प्रति सप्ताह कम से कम 70 लाख श्रमिकों की वृद्धि दर्शाती है।

वृद्धि दर का आंकड़ा उत्साहजनक, 2021-22 में दहाई अंक में वृद्धि की उम्मीदः पीएचडी चैंबर

नयी दिल्ली। एजेंसी

उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) ने मंगलवार को कहा कि देश की दूसरी तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर का 8.4 प्रतिशत का आंकड़ा उत्साह जगाने वाला है और चालू वित्त वर्ष में इसके दहाई अंक में रहने की उम्मीद है। पीएचडीसीसीआई के अध्यक्ष प्रदीप मुल्तानी ने कहा कि सरकार द्वारा किए गए सार्थक और सक्रिय सुधारों, भारतीय रिजर्व बैंक के सोच-समझकर उठाये गये कदमों, तेजी से चलाए गए टीकाकरण अभियान, बेहतर उपभोक्ता एवं कारोबारी धारणा और कमजोर तुलनात्मक आधार से अर्थव्यवस्था 2020-21 की बड़ी गिरावट से बाहर आ गयी है।

उन्होंने कहा कि उद्योग मंडल को वित्त वर्ष 2021-22 में आर्थिक वृद्धि दर 10.25 प्रतिशत रहने का अनुमान है। मुल्तानी ने कहा कि इस समय देश में खपत और निजी निवेश को समर्थन देने के लिए जिंसों की ऊंची कीमतों तथा कच्चे माल की कमी को दूर करने की आवश्यकता है। उद्योग मंडल एसोचैम ने कहा कि दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि की अच्छी बात यह है कि आर्थिक वृद्धि चौतरफा है। महामारी से प्रभावित ज्यादातर क्षेत्र पटरी पर लौटते दिख रहे हैं। उसने कहा, ''हालांकि कोरोनावायरस के नये स्वरूप के सामने आने के बाद वैश्विक स्तर पर पाबंदियों के साथ वृद्धि दर की गति को बनाये रखना एक चुनौती होगी।'' उद्योग मंडल ने कहा कि टीकाकरण पर ध्यान बनाये रखने और कोविड महामारी से बचाव के उपाय जारी रखना जरूरी है।

अमेरिका के बाद यूरोप में भी महंगाई चरम पर, टूटा 24 साल का रेकॉर्ड, जानिए क्या है वजह

नयी दिल्ली। एजेंसी

महंगाई की मार से भारत ही नहीं पूरी दुनिया त्रस्त है। यूरोप में महंगाई ने 24 साल का रेकॉर्ड तोड़ दिया है। तेल की बढ़ती कीमत से नवंबर मे यूरोपीय देशों में महंगाई चरम पर पहुंच गई। इन देशों में महंगाई 1997 के बाद नवंबर में सबसे तेजी से बढ़ी है। यूरो का इस्तेमाल करने वाले 19 देशों में नवंबर में सालाना महंगाई 4.9 फीसदी पर पहुंच गई। इनमें यूरोप की सबसे बड़ी इकॉनमी जर्मनी के साथ फ्रांस, इटली और स्पेन शामिल हैं। यूरोपियन यूनियन के स्टेटिस्टिक्स ऑफिस Eurostat के आंकड़ों में यह बात सामने आई हैं। यूरोपियन यूनियन ने 1 जनवरी 1999 को यूरोप को करेंसी के रूप में स्वीकार किया था। उससे दो साल पहले 1997 में महंगाई को आंकड़े लेने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। उसके बाद से नवंबर में यह रेकॉर्ड स्तर पर पहुंची है। इससे अक्टूबर में यह 4.1 फीसदी थी।

क्यों बढ़ रही है महंगाई

Eurostat के अनुमानों के मुताबिक नवंबर में तेल की कीमत में 27.4 फीसदी तेजी आई है। इस दौरान सर्विसेज इनफ्लेशन (services inflation) 2.7 फीसदी बढ़ा। Oxford Economics में अर्थशास्त्री Katharina Koenz ने एक रिसर्च नोट में लिखा कि मुख्य महंगाई में तेजी की मुख्य वजह तेल की ऊंची कीमत है लेकिन हैरानी की बात है कि कोर महंगाई में भी तेजी आई है। इसकी वजह जर्मन पैकेज होलिडे प्राइजेज में आई तेजी हो सकती है। इससे एक दिन पहले यूरोप की सबसे बड़ी इकॉनमी जर्मनी ने नवंबर में कंज्यूमर प्राइस में 5.2 फीसदी तेजी का अनुमान जताया था। जर्मनी में महंगाई करीब 30 साल में पहली बार सितंबर में 4 फीसदी के ऊपर पहुंची थी। अमेरिका में भी तेल और अन्य वस्तुओं की कीमत में तेजी के कारण कंज्यूमर प्राइस नवंबर में रेकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। इसमें 31 साल में सबसे ज्यादा सालाना तेजी आई है।

'पुराणों से आधुनिक ज्ञान'

'पुराणों को विद्यालयों में लागू करना क्यों अनिवार्य हो'

संतोष वाधवानी
रत्न विशेषज्ञ
अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष
एवं वास्तु एसोसिएशन
प्रदेश प्रवक्ता

पुराण शब्द का अर्थ ही है प्राचीन कथा, पुराण विश्व साहित्य के सबसे प्राचीन ग्रँथ हैं, उन में लिखित ज्ञान और नैतिकता की बातें आज भी प्रासंगिक, अमूल्य तथा मानव सभ्यता की आधारशिला हैं। वेदों की भाषा तथा शैली कठिन है, पुराण उसी ज्ञान के सहज तथा रोचक संस्करण हैं। उन में जटिल तथ्यों को कथाओं के माध्यम से समझाया गया है, पुराणों का विषय नैतिकता, विचार, भूगोल, खगोल, राजनीति, संस्कृति, सामाजिक परम्परायें, विज्ञान तथा अन्य बहुत से विषय हैं। विशेष तथ्य यह है कि पुराणों में देवी-देवताओं, राजाओं, और ऋषि-मुनियों के साथ साथ जन साधारण की कथाओं का भी उल्लेख किया गया हैं, जिस से पौराणिक काल के सभी पहलूओं का चित्रण मिलता है। महर्षि वेदव्यासजी ने अट्ठारह पुराणों का संस्कृत भाषा में संकलन किया है, ब्रह्मदेव, श्री हरि विष्णु भगवान् तथा भगवान् महेश्वर उन पुराणों के मुख्य देव हैं, त्रिमूर्ति के प्रत्येक भगवान स्वरूप को छः पुराण समर्पित किये गये हैं, इन अट्ठारह पुराणों के अतिरिक्त सोलह उप-पुराण भी हैं।

1. ब्रह्म पुराण

ब्रह्मपुराण सब से प्राचीन है, इस पुराण में दो सौ छियालीस अध्याय तथा चौदह हजार श्लोक हैं, इस ग्रंथ में ब्रह्माजी की महानता के अतिरिक्त सृष्टि की उत्पत्ति, गंगा अवतरण तथा रामायण और कृष्णावतार की कथायें भी संकलित हैं इस ग्रंथ से सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर सिन्धु घाटी सभ्यता तक की कुछ ना कुछ जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

2.पद्म पुराण

दूसरा हैं पद्मपुराण, जिसमें हैं पचपन हजार श्लोक और यह ग्रन्थ पाँच खण्डों में विभाजित किया गया है, जिनके नाम सृष्टिखण्ड, स्वर्गखण्ड, उत्तरखण्ड, भूमिखण्ड तथा पातालखण्ड हैं, इस ग्रंथ में पृथ्वी आकाश, तथा नक्षत्रों की उत्पति के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है, चार प्रकार से जीवों की उत्पत्ति होती है जिन्हें उदिभज, स्वेदज,अणडज तथा जरायुज की श्रेणी में रखा गया है, यह वर्गीकरण पूर्णतया वैज्ञानिक आधार पर है। भारत के सभी पर्वतों तथा नदियों के बारे में भी विस्तार से वर्णन है, इस पुराण में शकुन्तला दुष्यन्त से ले कर भगवान राम तक के कई पूर्वजों का इतिहास है, शकुन्तला दुष्यन्त के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम जम्बूदीप से भरतखण्ड और उस के बाद भारत पडा था यह पद्म पुराण हम सभी भाई-बहनों को पढ़ना चाहियें, क्योंकि इस पुराण में हमारे भूगौलिक और आध्यात्मिक वातावरण का विस्तृत वर्णन मिलता है।

3.विष्णु पुराण

तीसरा पुराण हैं विष्णुपुराण, जिसमें छः अँश तथा तेइस हजार श्लोक हैं, इस ग्रंथ में भगवान् श्री विष्णुजी, बालक ध्रुवजी तथा कृष्णावतार की कथायें संकलित हैं, इस के अतिरिक्त सम्राट पृथुजी की कथा भी शामिल है, जिसके कारण हमारी धरती का नाम पृथ्वी पडा था, इस पुराण में सूर्यवँशीयों तथा चन्द्रवँशीयों राजाओं का सम्पूर्ण इतिहास है।

उत्तरं यत्समुद्रस्य
हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम्।
वर्षं तद भारतं नाम
भारती यत्र सन्ततिः॥

भारत की राष्ट्रीय पहचान सदियों पुरानी है, जिसका प्रमाण विष्णु पुराण के इस श्लोक में मिलता है, साधारण शब्दों में इस का अर्थ होता है कि वह भूगौलिक क्षेत्र जो उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में सागर से जो घिरा हुआ है, यही भारत देश है तथा उस में निवास करने वाले हम सभी जन भारत देश की ही संतान हैं, भारत देश और भारत वासियों की इस से स्पष्ट पहचान और क्या हो सकती है? विष्णु पुराण वास्तव में ऐक ऐतिहासिक ग्रंथ है।

4. शिव पुराण

चौथा पुराण हैं शिवपुराण जिसे आदर से शिव महापुराण भी कहते हैं, इस महापुराण में चौबीस हजार श्लोक हैं, तथा यह सात संहिताओं में विभाजित है, इस ग्रंथ में भगवान् शिवजी की महानता तथा उन से सम्बन्धित घटनाओं को दर्शाया गया है इस ग्रंथ को वायु पुराण भी कहते हैं, इसमें कैलास पर्वत, शिवलिंग तथा रुद्राक्ष का वर्णन और महत्व विस्तार से दर्शाया गया है। सप्ताह के सातों दिनों के नामों की रचना, प्रजापतियों का वर्णन तथा काम पर विजय पाने के सम्बन्ध में विस्तार से वर्णन किया गया है। सप्ताह के दिनों के नाम हमारे सौर मण्डल के ग्रहों पर आधारित हैं, और आज भी लगभग समस्त विश्व में प्रयोग किये जाते हैं, भगवान् शिवजी के भक्तों को श्रद्धा और भक्ति से शिवमहापुराण का नियमित पाठ करना चाहिये भगवान् शंकरजी बहुत दयालु और भोले है, जो भी इस शीव पुराण को भाव से पढ़ता है उसका कल्याण निश्चित हैं।

5. भागवत पुराण

पाँचवा है भागवतपुराण, जिसमें अट्ठारह हजार श्लोक हैं, तथा बारह स्कंध हैं, इस ग्रंथ में अध्यात्मिक विषयों पर वार्तालाप है भागवत् पुराण में भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य की महानता को दर्शाया गया है, भगवान् विष्णुजी और भगवान् गोविन्द के अवतार की कथाओं को विसतार से दर्शाया गया हैं, इसके अतिरिक्त महाभारत काल से पूर्व के कई राजाओं, ऋषि मुनियों तथा असुरों की कथायें भी संकलित हैं। इस ग्रंथ में महाभारत युद्ध के पश्चात श्रीकृष्ण का देहत्याग, दूरिका नगरी के जलमग्न होने और यादव वँशियों के नाश तक का विवर्ण भी दिया गया है।

6. नारद पुराण

नारदपुराण छठा पुराण हैं जो पच्चीस हजार श्लोकों से अलंकृत है, तथा इस के भी भी दो भाग हैं दोनों भागो में सभी अट्ठारह पुराणों का सार दिया गया है, प्रथम भाग में मन्त्र तथा मृत्यु पश्चात के क्रम और विधान हैं, गंगा अवतरण की कथा भी विस्तार पूर्वक बतायी गयी है, दूसरे भाग में संगीत के सातों स्वरों, सप्तक के मन्द्र मध्य तथा तार स्थानों, मूर्छनाओं, शुद्ध एवम् कूट तानो और स्वरमण्डल का ज्ञान लिखित है। संगीत पद्धति का यह ज्ञान आज भी भारतीय संगीत का आधार है, जो पाश्चात्य संगीत की चकाचौंध से चकित हो जाते हैं, उनके लिये उल्लेखनीय तथ्य यह है कि नारद पुराण के कई शताब्दी पश्चात तक भी पाश्चात्य संगीत में केवल पाँच स्वर होते थे, तथा संगीत की थ्योरी का विकास शून्य के बराबर था, मूर्छनाओं के आधार पर ही पाश्चात्य संगीत के स्केल बने हैं, सभी संगीत के प्रेमी जो संगीत को ही अपना केरियर समझ लिया हो, या संगीत और अध्यात्म को साथ में देखने वाले ब्रह्म पुरूष को नारद पुराण को जरूर पढ़ना चाहियें।

7. मार्कंडेय पुराण

साँतवा है मार्कण्डेयपुराण, जो अन्य पुराणों की अपेक्षा सबसे छोटा पुराण है, मार्कण्डेय पुराण में नौ हजार श्लोक हैं तथा एक सो सडतीस अध्याय हैं, इस ग्रंथ में सामाजिक न्याय और योग के विषय में ऋषिमार्कण्डेयजी तथा ऋषि जैमिनिजी के मध्य वार्तालाप है इस के अतिरिक्त भगवती दुर्गाजी तथा भगवान् श्रीकृष्ण से जुड़ी हुयी कथायें भी संकलित हैं, सभी ब्रह्म समाज को यह पुराण पढ़नी चाहिये, कम से कम मार्कण्डेयजी ऋषि के वंशज इस पुराण को थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ने की कोशिश करनी चाहिये मार्कण्डेय पुराण के अध्ययन से आध्यात्मिक अक्षय सुख की प्राप्ति होती है।

8. अग्नि पुराण

आठवाँ है अग्निपुराण, अग्नि पुराण में तीन सौ तैयासी अध्याय तथा पन्द्रह हजार श्लोक हैं, इस पुराण को भारतीय संस्कृति का ज्ञानकोष या आज की भाषा में विकीपीडिया कह सकते है। इस ग्रंथ में भगवान् मत्स्यावतार का वर्णन है, रामायण तथा महाभारत काल की संक्षिप्त कथायें भी संकलित हैं, इसके अतिरिक्त कई विषयों पर वार्तालाप है जिन में धनुर्वेद, गान्धर्व वेद तथा आयुर्वेद मुख्य हैं, धनुर्वेद, गान्धर्व वेद तथा आयुर्वेद को उप-वेद भी कहा जाता है।

9. भविष्य पुराण

नवमा है भविष्यपुराण, भविष्य पुराण में एक सौ उनतीस अध्याय तथा अट्ठाईस श्लोक हैं, इस ग्रंथ में सूर्य देवता का महत्व, वर्ष के बारह महीनों का निर्माण, भारत के सामाजिक, धार्मिक तथा शैक्षिक विधानों और भी कई विषयों पर वार्तालाप है इस पुराण में साँपों की पहचान, विष तथा विषदंश सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गयी है, इस भविष्य पुराण की कई कथायें बाईबल की कथाओं से भी मेल खाती हैं, भविष्य पुराण में पुराने राजवँशों के अतिरिक्त भविष्य में आने वाले नन्द वँश, मौर्य वँशों का भी वर्णन है। इस के अतिरिक्त विक्रम बेताल तथा बेताल पच्चीसी की कथाओं का विवरण भी है, भगवान् श्रीसत्य नारायण की कथा भी इसी पुराण से ली गयी है, यह भविष्य पुराण भारतीय इतिहास का महत्वशाली स्त्रोत्र है, जिस पर शोध कार्य करना चाहिये और इसके उपदेश हर आज के क्षात्र-क्षात्राओं को पढ़ाना चाहिये और प्रथम क्लास से ही, शिक्षा से जुड़े समस्त अध्यापक एवम् अध्यापिका को इस भविष्य पुराण नामक पुराण को अवश्य पढ़ना चाहियें, ताकि आपकी समझ बढे, और समाज में अध्यात्म जागृति लायें।

10. ब्रह्मवैवर्त पुराण

दसवाँ पुराण है ब्रह्मावैवर्तपुराण, जो अट्ठारह हजार श्लोकों से अलंकृत है, तथा दो सौ अट्ठारह अध्याय हैं, इस ग्रंथ में ब्रह्माजी, गणेशजी, तुलसी माता, सावित्री माता, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता तथा भगवान् श्रीकृष्ण की महानता को दर्शाया गया है तथा उन से जुड़ी हुई कथायें संकलित हैं, इस पुराण में आयुर्वेद सम्बन्धी ज्ञान भी संकलित है, जो आयुर्वेद और भारतीय परम्परा में निरोगी काया के विषय पर गंभीर है, उसे यह ब्रह्मावैवर्त पुराण आपका पथ प्रदर्शक बनेगा।

11. लिंग पुराण

ग्यारहवा है लिंगपुराण, इस पावन लिंग पुराण में ग्यारह हजार श्लोक और एक सौ तरसठ अध्याय हैं, सृष्टि की उत्पत्ति तथा खगौलिक काल में युग, कल्प की तालिका का वर्णन है, भगवान् सूर्यदेव के सूर्य के वंशजों में राजा अम्बरीषजी हुयें रामजी इन्हीं राजा अम्बरीषजी के कूल में अवतार हुआ था, राजा अम्बरीषजी की कथा भी इसी पुराण में लिखित है, इस ग्रंथ में अघोर मंत्रों तथा अघोर विद्या के सम्बन्ध में भी उल्लेख किया गया है।

12. वराह पुराण

बाहरवां पुराण हैं वराहपुराण, वराह पुराण में दो सौ सत्रह स्कन्ध तथा दस हजार श्लोक हैं, इस ग्रंथ में भगवान् श्री हरि के वराह अवतार की कथा, तथा इसके अतिरिक्त भागवत् गीता महात्म्य का भी विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है इस पुराण में सृष्टि के विकास, स्वर्ग, पाताल तथा अन्य लोकों का वर्णन भी दिया गया है, श्राद्ध पद्धति, सूर्य के उत्तरायण तथा दक्षिणायन विचरने, अमावस और पूर्णमासी के कारणों का वर्णन है। महत्व की बात यह है कि जो भूगौलिक और खगौलिक तथ्य इस पुराण में संकलित हैं। वही तथ्य पाश्चात्य जगत के वैज्ञानिकों को पंद्रहवी शताब्दी के बाद ही पता चले थे, सभी सनातन धर्म को मानने वाले भाई-बहनों को यह वराह पुराण को अवश्य पढ़ना चाहियें, जो भक्त अपने जीवन में जीते जी स्वर्ग की कल्पना करता है, उसके लिये वराह पुराण अतुल्य है इसमें स्वर्ग-नरक का भगवान् श्री वेदव्यासजी ने बखूबी वर्णन किया है।

13. स्कंद पुराण

तेहरवां पुराण हैं सकन्दपुराण, सकन्द पुराण सब से विशाल पुराण है, तथा इस पुराण में अक्यासी हजार श्लोक और छः खण्ड हैं, सकन्द पुराण में प्राचीन भारत का भूगौलिक वर्णन है जिस में सत्ताईस नक्षत्रों, अट्ठारह नदियों, अरुणाचल प्रदेश का सौंदर्य, भारत में स्थित भगवान् भोलेनाथ के बारह ज्योतिर्लिंगों, तथा गंगा अवतरण के आख्यान शामिल हैं, इसी पुराण में स्याहाद्री पर्वत श्रंखला तथा कन्या कुमारी मन्दिर का उल्लेख भी किया गया है इसी पुराण में सोमदेव, तारा तथा उन के पुत्र बुद्ध ग्रह की उत्पत्ति की अलंकारमयी कथा भी है।

14. वामन पुराण

चौदहवां पुराण है वामनपुराण, वामन पुराण में निन्यानवें अध्याय तथा दस हजार श्लोक हैं, एवम् दो खण्ड हैं, इस पुराण का केवल प्रथम खण्ड ही उपलब्ध है इस पुराण में भगवान् के वामन अवतार की कथा विस्तार से कही गयी हैं, जो भरूचकच्छ (गुजरात) में हुआ था, इस के अतिरिक्त इस ग्रंथ में भी सृष्टि, जम्बूद्वीप तथा अन्य सात द्वीपों की उत्पत्ति, पृथ्वी की भूगौलिक स्थिति, महत्वशाली पर्वतों, नदियों तथा भारत के खण्डों का जिक्र है।

15. कूर्म पुराण

पन्द्रहवां पुराण है कुर्मपुराण, कुर्म पुराण में अट्ठारह हजार श्लोक तथा चार खण्ड हैं, इस पुराण में चारों वेदों का सार संक्षिप्त रूप में दिया गया है, कुर्म पुराण में कुर्म अवतार से सम्बन्धित सागर मंथन की कथा विस्तार पूर्वक लिखी गयी है इस में ब्रह्माजी, शिवजी, विष्णुजी, पृथ्वी माता, गंगा मैया की उत्पत्ति, चारों युगों के बारे में सटीक जानकारी, मानव जीवन के चार आश्रम धर्मों, तथा चन्द्रवँशी राजाओं के बारे में भी विस्तार से वर्णन है।

16. मत्स्य पुराण

सोलहवां पुराण है मतस्यपुराण, मतस्य पुराण में दो सौ नब्बे अध्याय तथा चौदह हजार श्लोक हैं, इस ग्रंथ में मतस्य अवतार की कथा का विस्तरित उल्लेख किया गया है, सृष्टि की उत्पत्ति और हमारे सौर मण्डल के सभी ग्रहों चारों युगों तथा चन्द्रवँशी राजाओं का इतिहास वर्णित है, कच, देवयानी, शर्मिष्ठा तथा राजा ययाति की रोचक कथा भी इसी मतस्य पुराण में है, सामाजिक विषयों के जानकारी के इच्छुक भाई-बहनों को मतस्य पुराण को जरूर पढ़ना चाहियें।

17. गरुड़ पुराण

सत्रहवां पुराण है गरुड़पुराण, गरुड़ पुराण में दो सौ उनअस्सी अध्याय तथा अट्ठारह हजार श्लोक हैं; इस ग्रंथ में मृत्यु पश्चात की घटनाओं, प्रेत लोक, यम लोक, नरक तथा चौरासी लाख योनियों के नरक स्वरुपी जीवन के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस पुराण में कई सूर्यवँशी तथा चन्द्रवँशी राजाओं का वर्णन भी है, साधारण लोग इस ग्रंथ को पढ़ने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि? इस ग्रंथ को किसी सम्बन्धी या परिचित की मृत्यु होने के पश्चात ही पढ़वाया जाता है। वास्तव में इस पुराण में मृत्यु पश्चात पुनर्जन्म होने पर गर्भ में स्थित भ्रूण की वैज्ञानिक अवस्था सांकेतिक रूप से बखान की गयी है, जिसे वैतरणी नदी की संज्ञा दी गयी है, उस समय तक भ्रूण के विकास के बारे में कोई भी वैज्ञानिक जानकारी नहीं थी, तब हमारे इसी गरूड पुराण ने विज्ञान और वैज्ञानिकों को दिशा दी इस पुराण को पढ़ कर कोई भी मानव नरक में जाने से बच सकता है।

18. ब्रह्मांड पुराण

अट्ठारहवां और अंतिम पुराण हैं ब्रह्माण्डपुराण, ब्रह्माण्ड पुराण में बारह हजार श्लोक तथा पूर्व, मध्य और उत्तर तीन भाग हैं, मान्यता है कि अध्यात्म रामायण पहले ब्रह्माण्ड पुराण का ही एक अंश थी जो अभी एक प्रथक ग्रंथ है, इस पुराण में ब्रह्माण्ड में स्थित ग्रहों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है,कई सूर्यवँशी तथा चन्द्रवँशी राजाओं का इतिहास भी संकलित है,सृष्टि की उत्पत्ति के समय से ले कर अभी तक सात मनोवन्तर बीत चुके हैं जिन का विस्तरित वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। भगवान् श्री परशुरामजी की कथा भी इस पुराण में दी गयी है, इस ग्रँथ को विश्व का प्रथम खगोल शास्त्र कह सकते है, भारत के ऋषि इस पुराण के ज्ञान को पूरे ब्रह्माण्ड तक ले कर गये थे, जिसके प्रमाण हमें मिलते रहे है, हिन्दू पौराणिक इतिहास की तरह अन्य देशों में भी महामानवों, दैत्यों, देवों, राजाओं तथा साधारण नागरिकों की कथायें प्रचिलित हैं, कईयों के नाम उच्चारण तथा भाषाओं की विभिन्नता के कारण बिगड़ भी चुके हैं जैसे कि हरिकुल ईश से हरकुलिस, कश्यप सागर से केस्पियन सी, तथा शम्भूसिहं से शिन बू सिन आदि बन गये।

वंशों से जोडा है, इस कारण पौराणिक कथायें इतिहास, साहित्य तथा दंत कथाओं का मिश्रण हैं। रामायण, महाभारत तथा पुराण हमारे प्राचीन इतिहास के बहुमूल्य स्त्रोत्र हैं, जिनको केवल साहित्य समझ कर अछूता छोड़ दिया गया है,इतिहास की विक्षप्त श्रंखलाओं को पुनः जोड़ने के लिये हमें पुराणों तथा महाकाव्यों पर शोध करना होगा, पढ़े-लिखे आज की युवा पीढ़ी को यह आव्हान है, जो छुट गया उसे जाने दो, जो अध्यात्म विरासत बची है, उसे समझने की कोशिश करों, पुराणों में अंकीत उपदेशों को अपने जीवन में आत्मसात करें।

जय सनातन धर्म।

मोटर्स बनाने के 30 वर्षों के अनुभव का इस्तेमाल करते हुए

शक्ति पम्पस ईवी मोटर्स, चार्जर्स, कंट्रोलर्स और ड्राइव्स के निर्माण में कदम रखने को तैयार

कंपनी के बोर्ड ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लगने वाली मोटर्स, चार्जर्स, कंट्रोलर्स और ड्राइव्स निर्माण के लिए एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को शामिल करने की मंजूरी दी

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

शक्ति पंप्स (इंडिया) लिमिटेड ने अपने मोटर्स बनाने के 30 वर्षों के अनुभव का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मोटर्स, चार्जर्स, कंट्रोलर्स और मल्टी - एप्लिकेशन कंपोनेंट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स (वीएफडी) के निर्माण के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्षेत्र में कदम रखने की घोषणा की। इसके लिए हाल ही में हुई शक्ति पम्पस (इं) लिमिटेड की बोर्ड बैठक में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को शामिल करने को मंजूरी दी है। बोर्ड मीटिंग के उपरांत शक्ति पंप्स (इंडिया) लिमिटेड के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश पाटीदार ने कहा - 'शक्ति पंप्स (इंडिया) लिमिटेड के पास जहां इलेक्ट्रिक मोटर्स बनाने का 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है वहीं पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट बनाने का 5 वर्षों का अनुभव है। इसी अनुभव और विशेषज्ञता के विश्वास के साथ अब हम पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के माध्यम से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बैटरी चार्जर, ईवी कंट्रोलर और ईवी मोटर्स का निर्माण और आपूर्ति करेंगे जिनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाज़ार को जरूरत है। शक्ति पम्पस (इंडिया) लिमिटेड, भारत की सबसे बड़ी सबमर्सिबल सोलर पम्पस, मोटोराइज्ड पम्पस की निर्माता और आपूर्तिकर्ता कंपनी है। 1982 में एक छोटी सी शुरुआत के साथ, शक्ति पम्पस एनर्जी एफिशियेंट सबमर्सिबल पम्पस और मोटर्स के निर्माण में अग्रणी है। शक्ति पंप्स ने हाल ही में सिम्हा 2.0 यूनिवर्सल ड्राइव लॉन्च किया है, सिम्हा 2.0 एक अनूठा उत्पाद है जो सोलर पम्पस को पॉवर देता है. कंपनी ने मिजोरम में भारत का पहला उच्च एचपी सोलर पंपिंग स्टेशन भी स्थापित किया है और हाल ही में पूरे पंजाब में सोलर पम्पस की स्थापना को समय से पहले पूरा करने के लिए सम्मानित किया गया था। शक्ति पंप्स की मध्य प्रदेश के पीथमपुर में दो फैक्ट्रियां हैं. भारत में सोलर पम्पस बाजार में अग्रणी स्थिति के साथ, शक्ति वैश्विक स्तर पर 100 से अधिक देशों में पंपिंग उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला का निर्यात करती है। कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है।

वित्त वर्ष 2022 में उर्वरकों की आपूर्ति के लिए रूसी फर्म के साथ करार किया

नयी दिल्ली। एजेंसी

कम से कम चार भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) ने चालू वित्त वर्ष में डीएपी सहित पांच प्रकार के उर्वरकों की आपूर्ति करने के लिए रूसी फर्म फॉस एग्रो के साथ एक दीर्घकालिक समझौता किया है। उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को राज्यसभा में यह जानकारी दी। मंडाविया ने उच्च सदन को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि मोरक्को, सऊदी अरब,रूस सहित विभिन्न देशों से भारत को डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) और इसके कच्चे माल की उचित कीमतों पर नियमित और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा, ''चार भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों और रूसी कंपनी फॉस एग्रो के बीच वर्ष 2021/2022 में डीएपी सहित पांच प्रकार के उर्वरकों की आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।'' मंत्री ने कहा कि उर्वरकों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए, सरकार ने हाल ही में मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड यूनिट-दो को 1.20 लाख टन प्रति वर्ष उत्पादन की अनुमति दी थी। इसका उत्पादन अक्टूबर में शुरू हुआ था। उन्होंने देश में उर्वरकों की किसी भी कमी से इनकार करते हुए बताया कि देश में डीएपी की पर्याप्त और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किये गये हैं। विभिन्न राज्यों में उर्वरक पहुंचाना सुनिश्चित करने के संदर्भ में, मंत्री ने - राज्यसभा में अपने लिखित उत्तर में - कहा कि केंद्र एक नियंत्रण कक्ष और वेब प्लेटफॉर्म के माध्यम से राज्य सरकारों, उर्वरक कंपनियों और रेलवे के साथ चौबीसों घंटे बातचीत चला रहा है। उन्होंने कहा कि विनिर्माताओं, बंदरगाहों और रेलवे जैसे अंशधारकों को उर्वरकों के उत्पादन, लोड और लक्षित गंतव्यों तक ले जाने के लिए अपने अधिकतम क्षमता के साथ काम करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा, आयातित डीएपी खेप की ढुलाई और यात्रा समय की दैनिक आधार पर निगरानी की जा रही है और समय-समय पर उपयुक्त हस्तक्षेप किए जा रहे हैं।

दुबई एक्सपो में भारत का पवेलियन बना आकर्षण का केंद्र

दुबई। एजेंसी

पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ सजावटी और अन्य घरेलू सामानों का उत्पादन करने वाली स्टार्टअप बिया की युवा संस्थापक इंडिया पवेलियन के 'इंडिया इनोवेशन हब' में अपनी खुशी को छिपा नहीं पा रही हैं। उनके काम को दुबई एक्सपो में काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। प्रवेश द्वारा लगी लंबी कतारों से पता चलता है कि एक्सपो-2020 में भारतीय पवेलियन के प्रति काफी उत्साह देखा जा रहा है। कंपनी के दो संस्थापकों में से एक पूजा सिंह कहती हैं कि इंस्टाग्राम पर केवल चार घंटों में उनके 100 विजिटर और 50 से अधिक फॉलोअर्स हो गए हैं। उनकी कारोबारी भागीदार प्रतीशा मलिक भी इस बात से सहमति जताती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने और भारतीय यूनिकॉर्न (एक अरब डॉलर से अधिक मूल्यांकन) की संख्या में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का लगातार जिक्र करते रहे हैं। ऐसे में भारत ने दुबई एक्सपो में अपने मंडप में बड़ी संख्या में नए उद्यमों को जगह देने का प्रयास किया है।

दुबई एक्सपो का आयोजन अक्टूबर-मार्च के दौरान होता है। पवेलियन के संचालकों का कहना है कि अब तक 84 ऐसे स्टार्टअप को जगह दी गई है और एक्सपो खत्म होने तक उनकी संख्या 500 तक जा सकती है। हालांकि, स्टार्टअप इस विशाल स्थल में भारत के पवेलियन में लगाए गए बहुआयामी प्रदर्शन का सिर्फ एक पहलू हैं। इसके अलावा कई अन्य भागीदार भी हैं, जिनमें एमिरेट्स जैसी बड़ी कंपनियां और संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन शामिल हैं। भारतीय पवेलियन में योग और देश की विविध संस्कृति को भी दर्शाया गया है। साथ ही इसमें भारत को अवसरों की जमीन के रूप में भी पेश किया गया है। चूंकि संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के साथ भारत के हमेशा से गर्मजोशी वाले रिश्ते रहे हैं, ऐसे में पवेलियन का एक हिस्सा दोनों की दोस्ती के लिए 'समर्पित' किया गया है।

कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन अक्टूबर में 7.5 प्रतिशत बढ़ा

सबसे ज्यादा इन क्षेत्रों ने दिखाया असर

इंदौर। देश के कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज से अच्छी खबर है। कोयला, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद और सीमेंट क्षेत्र के अच्छे प्रदर्शन की मदद से आठ ढांचागत क्षेत्रों का उत्पादन अक्टूबर में 7.5 प्रतिशत बढ़ गया। पीटीआई की खबर के मुताबिक, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक इन प्रमुख क्षेत्रों का उत्पादन अक्टूबर में खासा सुधरा है। सितंबर में यह 4.5 प्रतिशत की दर से बढ़ा था जबकि अक्टूबर 2020 में इसकी वृद्धि दर में 0.5 फीसदी का सिकुड़न दर्ज किया गया था।

औद्योगिक उत्पादन के नजरिये से अहम

खबर के मुताबिक, आठ बुनियादी उद्योगों- कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली के उत्पादन को देश के औद्योगिक उत्पादन के नजरिये से खासा अहम माना जाता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (ध्ध्ह्) में इन उद्योगों का भारांश 40.27 प्रतिशत है। चालू वित्त वर्ष के पहले सात महीनों यानी अप्रैल-अक्टूबर में बुनियादी उद्योगों का उत्पादन 15.1 प्रतिशत बढ़ा है। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में बुनियादी उद्योगों का उत्पादन 12.6 प्रतिशत घटा था।

अक्टूबर 2021 में अलग-अलग सेक्टर की ग्रोथ रेट

अक्टूबर 2021 में कोयला 14.6 प्रतिशत, प्राकृतिक गैस 25.8 प्रतिशत, रिफाइनरी उत्पाद 14.4 प्रतिशत और सीमेंट 14.5 प्रतिशत की दर से बढ़ा। लेकिन कच्चा तेल उत्पादन 2.2 प्रतिशत, उर्वरक 0.04 प्रतिशत, स्टील 0.9 प्रतिशत और बिजली उत्पादन 2.8 प्रतिशत गिर गया।

वाहन उत्पादन में गिरावट का दिख सकता है असर

इन आंकड़ों पर इक्रा लिमिटेड की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि आठ प्रमुख उद्योगों का अक्टूबर में उत्पादन मुख्य रूप से रिफाइनरी उत्पादों, कोयला, सीमेंट एवं बिजली क्षेत्रों के दम पर बढ़ा है। उन्होंने कहा कि वाहन उत्पादन में 22 फीसदी की गिरावट आने से आईआईपी 2.5 प्रतिशत से भी नीचे आ सकता है।

एमएसएमई के लिए चीन से दूर हो रहे निवेश को आकर्षित करने की जरूरत

नयी दिल्ली। एजेंसी

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री नारायण राणे ने मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से एमएसएमई इकाइयों की विनिर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए चीन से बाहर निकल रहे विदेशी निवेश को आकर्षित करने की भरोसेमंद नीति बनाने का अनुरोध किया। आधिकारिक बयान के अनुसार राणे ने वित्त मंत्री से मुलाकात कर अपने मंत्रालय का बजट बढ़ाने और प्रमुख योजनाएं जारी रखने के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कोविड-19 महामारी से प्रभावित एमएसएमई इकाइयों के लिये कर्ज जरूरत के मुद्दे को भी रखा। बयान के अनुसार, ''मंत्री ने वित्त मंत्री के साथ मुलाकात की और देश में एमएसएमई की विनिर्माण क्षमता बढ़ाने को लेकर चीन से बाहर निकल रहे विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिये भरोसेमंद नीति की जरूरत बतायी।''

1 दिसंबर से हुए ये महत्वपूर्ण बदलाव, जो अपकी जेब पर डालेंगे बड़ा प्रभाव

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

हर महीने का पहला दिन आमतौर पर बदलाव लाता है। इसलिए जरूरी है कि आप उनके बारे में पहले से जान लें 1 दिसंबर से क्या बदलने जा रहा है। एलपीजी सिलेंडर के भाव बढ़े-एलपीजी सिलेंडर के सस्ता होने की उम्मीदों को आज झटका लगा है। गैस सिलेंडर आज से 100 रुपये महंगा हो गया है। राहत की बात ये थी कि यह बढ़ोतरी कमर्शियल सिलेंडर में ही हुई है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया। पेट्रोलियम कंपनियों ने यह बढ़ोतरी कमर्शियाल सिलेंडर की कीमतों में की है। पिछले महीने 266 रुपये महंगा हुआ था और अब इसमें 100 रुपये की वृद्धि की गई है। आज भी दिल्ली में कमर्शियाल सिलेंडर 2100 रुपये के पार है। दो महीने पहले यह 1733 रुपये का था। मुंबई में 19 किलो का सिलेंडर 2051 रुपये का हो गया है। वहीं, कोलकाता में 19 किलो वाला इंडेन गैस सिलेंडर 2174.50 रुपये का हो गया है। चेन्नई में अब 19 किलो वाले सिलेंडर के लिए 2234 रुपये खर्च करने पड़ेंगे।

आईटीआर फाइल करने की समय सीमा

31 दिसंबर तक आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। क्योंकि, कोविड -19 महामारी के मद्देनजर करदाताओं के सामने आने वाली कठिनाइयों के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कराधान बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समय सीमा वित्त वर्ष 2020-21 को 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया था।

एसबीआई क्रेडिट कार्ड ईएमआई लेनदेन महंगा

एसबीआई की क्रेडिट कार्ड ईएमआई सुविधा पर उत्पाद खरीदने वाले ग्राहक 1 दिसंबर 2021 से महंगे होने जा रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एसबीआई कार्ड अब आज से सभी ईएमआई खरीद लेनदेन पर रू. 99 प्लस टैक्स का प्रसंस्करण शुल्क लगाएंगे। रू. 99 का प्रसंस्करण शुल्क केवल उन लेनदेन पर लिया जाएगा, जिन्हें सफलतापूर्वक समान मासिक किस्तों या ईएमआई लेनदेन में परिवर्तित कर दिया गया है।

पीएनबी ने बचत खाते की ब्याज दरों में किया संशोधन

पंजाब नेशनल बैंक ने 1 दिसंबर 2021 से बचत खाते की ब्याज दर में कटौती करने के अपने फैसले की घोषणा की है। पीएनबी ने बचत खाते में जमा राशि पर ब्याज दर को 10 लाख रुपये से कम और 5 आधार अंकों (बीपीएस) से कम कर दिया है। बचत खाते में ?10 लाख से कम की शेष राशि पर ब्याज दर 2.80ञ होगी। वहीं, 10 लाख और उससे अधिक की शेष राशि पर ब्याज दर 2.85% प्रति वर्ष होगी।

14 साल बाद माचिस की कीमतों में बढ़ोतरी

भारत में 14 वर्षों के बाद माचिस की कीमतों में वृद्धि देखी जाएगी। माचिस की खुदरा कीमत 1 दिसंबर, 2021 से शुरू होने वाले रू. 1 के मौजूदा मूल्य से दोगुनी होकर रू. 2 हो जाएगी। यह 2007 के बाद की बात है। वहीं, प्रति बॉक्स माचिस की तीलियों की संख्या भी बढ़ रही है।

जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करने पर रुक सकती है पेंशन

जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की समय सीमा 30 नवंबर थी, और यदि दस्तावेज जमा नहीं किया जाता है, तो पेंशन संवितरण प्राधिकरण (पीडीए) पेंशनभोगी के देय धन का वितरण नहीं कर सकते हैं।

आधार से लिंक नहीं कराने पर रुकेगा EPF का पैसा

यदि आप कॉर्पोरेट क्षेत्र के कर्मचारी हैं और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में आपका खाता है, तो आपको अपने खाते को अपने आधार से लिंक करना होगा। आधार को UAN से जोड़ने की अंतिम तिथि 30 नवंबर थी।

क्रिप्टोकरंसी में छोटे निवेशकों की पूंजी डूबने का डर

मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिग जैसे कई खतरे

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

आभाषी मुद्रा (क्रिप्टोकरंसी) को लेकर सरकार ने फिर से सख्त संदेश दिया है। सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में स्पष्ट कहा कि सरकार की देश में क्रिप्टोकरंसी बिटक्वाइन को करंसी के रूप में मान्यता देने की कोई योजना नहीं है। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास कई मौकों पर कह चुके हैं कि क्रिप्टोकरंसी में छोटे निवेशकों की पूंजी डूबने के साथ मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिग जैसे कई खतरे मौजूद हैं। सरकार शीतकालीन सत्र में क्रिप्टोकरंसी के नियमन के लिए बिल लाने की तैयारी में है। वित्त मंत्री के इस स्ष्टीकरण के पहले क्रिप्टोकरंसी उद्योग में इस तरह की चर्चा थी कि सरकार बिटक्वाइन पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगाएगी। वित्त मंत्री ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में यह भी कहा कि सरकार बिटक्वाइन के लेनदेन के आंकड़े एकत्र नहीं करती है। उल्लेखनीय है कि मौजूदा समय में देश में क्रिप्टोकरंसी के उपयोग के संबंध में न तो कोई प्रतिबंध है और न ही कोई नियमन है। हालांकि, रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय समय-समय पर यह चेतावनी देते रहे हैं कि नियमन नहीं होने से क्रिप्टोकरंसी में निवेश करना खतरे से खाली नहीं है और निवेशक इससे बचकर रहें।

सुप्रीम कोर्ट ने दी थी राहत

वर्ष 2018 में रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने क्रिप्टोकरंसी पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज रिजर्व बैंक के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए जहां शीर्ष अदालत ने वर्ष 2020 में आरबआई के प्रतिबंध को हटा दिया था। इसके बाद भी रिजर्व बैंक समय-समय पर निवेशकों के हित में क्रिप्टोकरंसी को लेकर चेतावनी जारी करता रहा है। अब क्रिप्टोकरंसी बिल के जरिये कानून बनानकर नियमन के दायरे में लाने की तैयारी है।

आरबीआई को छोटे निवेशकों की चिंता

दास का कहना है कि आरबीआई की चिंता छोटे निवेशकों को लेकर है। उनका कहना है कि भारत में क्रिप्टोकरंसी में 500 रुपये से लेकर दो हजार रुपये तक निवेश करने वाले लोगों की संख्या 80 फीसदी है और इनमें भी युवाओं की संख्या अधिक है। उनका कहना है कि क्रिप्टोकरंसी में उतार-चढ़ाव तेज होता है। इसमें इन निवेशकों की पूंजी डूबने की आशंका अधिक होती है।

संसदीय समिति ले रही राय

पूर्व वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा के नेतृत्व में एक ससंदीय समिति भारत में क्रिप्टोकरंसी पर विशेषज्ञों की राय ले रही है। हालांकि, समिति की पिछले दिनों बैठक में किसी मुद्दे पर एक राय नहीं बन सकी। समिति का मानना है कि क्रिप्टोकरंसी को नियमन के दायरे में लाना निवेशकों के हित में जरूरी है। लेकिन इसपर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने से भारत इसमें मिलने वाले वैश्विक अ?वसरों में पीछो रह सकता है। ऐसे में दोनों मुद्दों को ध्यान में रखकर कारगर उपाय की तलाश की जा रही है।

मुठ्टी भर क्रिप्टोकरंसी ही रह जाएंगी

आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने पिछले दिनों कहा था कि मौजूदा समय में दुनिया में हजारों की संख्या में क्रिप्टोकरंसी हैं, लेकिन अगले कुछ साल में एक-दो या मुठ्टी भर क्रिप्टोकरंसी ही रह जाएंगी। एक अनुमान के अनुसार मौजूदा समय में छह हजार से ज्यादा क्रिप्टोकरंसी दुनिया में हैं।

परंपरागत मुद्रा नहीं बन पाएगी

पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा का कहना है कि क्रिप्टोकरंसी के बारे में इस समय भ्रम की स्थिति है। उन्होंने कहा, हर सरकार इसे लेकर संशयग्रस्त है और क्रिप्टोकरंसी परंपरागत मुद्रा की जगह नहीं ले पाएगी। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि क्रिप्टोकरंसी को लेकर जताई जा रही तमाम आपत्तियों के बावजूद यह बनी रहने वाली है और अगले पांच वर्षों में यह मुख्यधारा की प्रौद्योगिकी बन जाएगी।

सस्ते और नॉन-ब्रांडेड उत्पाद को तरजीह दे रहे हैं उपभोक्ता

डिटर्जेंट बार, वाशिंग पाउडर, नूडल्स में ब्रांड का दबदबा कायम

नई दिल्ली। एजेंसी

देश में आसमान छूती महंगाई के बीच घर का बजट बिगड़ने से बचाने के लिए उपभोक्ता सस्ते और नान-ब्रांडेड उत्पाद को तरजीह दे रहे हैं। मार्केट रिसर्च कंपनी कंतार की रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है। रिपोर्ट के अनुसार, उपभोक्ताओं ने सितंबर तिमाही के दौरान साबुन, दूध से बने उत्पाद, खाद्य तेल और घरेलू सफाई में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों सहित लगभग आधा दर्जन सामान नान-ब्रांडेड कंपनियों के या उन ब्रांड के खरीदे हैं जिनके उत्पाद के विकल्प बाजार में उपलब्ध नहीं हैं। इतना ही नहीं उपभोक्ता बड़े पैक की जगह 5 से 10 रुपये वाले छोटे पैक अधिक खरीदें। खरीदारी में बदलाव का यह रुझान शहरों के साथ गांवों में भी देखने को मिला।

महंगाई बढ़ने से रुझान में बदलाव आया

पिछले साल कोरोना महामारी के बाद से उपभोक्ताओं के खरीदारी पैटर्न में बड़ा बदलाव आया है। उपभोक्ता अपनी जरूरी के सामान

ब्रांडेड कंपनियों की जगह नान-ब्रांडेड और स्थानीय कंपनियों के खरीद रहे हैं। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि उत्पाद की ऊंची कीमतों के चलते बढ़ता घरेलू खर्च इसकी मुख्य वजह है। उपभोक्ता अपने खर्च पर लगाम लगाने के लिए ब्रांडेड की जगह नान-ब्रांडेड और सस्ते उत्पाद को तरजीह दे रहे हैं।

कंपनियों ने उत्पादों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की

कोरोना महामारी के बाद से अधिकांश कंपनियों ने मुद्रास्फीति के दबाव में अपने उत्पादों की कीमतों में भारी वृद्धि की है। कई कंपनियों ने बीते एक साल में दो या उससे अधिक बार कीमत में बढ़ोतरी की है। वहीं, बहुत सारी कंपनियों ने अगली तिमाही में भी कीमतों में बढ़ोतरी का संकेत दिए हैं। एक साल पहले से खाद्य तेल, ईंधन, सब्जी, दवा, चाय आदि की कीमतों में 50% से अधिक की वृद्धि हुई है जबकि पैकेजिंग सामग्री की कीमतों में पिछले वर्ष की तुलना में 30-35ञ की वृद्धि हुई है।

कई जगह ब्रांडेड का दबदबा कायम

रिपोर्ट के अनुसार, कोरोना महामारी के बाद जरूरी सस्ते सामान की मांग बढ़ी है लेकिन कई सेगमेंट अभी भी ऐसे हैं जिनमें ब्रांडेड कंपनियों का दबदबा कायम है। उपभोक्ता ब्रांडेड कंपनी से ही डिटर्जेंट बार, वाशिंग पाउडर, नूडल्स और चाय खरीदारी कर रहे हैं। इसके साथ ही हेल्थ से जुड़े उत्पाद में अभी भी ब्रांडेड कंपनियों पर भरोसा कायम है। हां, खाद्य तेल, चावल, दाल आदि के लिए उपभोक्ताओं ने जरूर स्थानीय उत्पाद या नान-ब्रांडेड कंपनियों की ओर रुख किया है।

मुनाफा के लिए मात्रा पर कैंची

खाद्य उत्पाद के दाम आसमान छू रहे हैं और कंज्यूमर उत्पाद बनाने वाली कंपनियां मार्जिन बचाने के लिए मात्रा पर कैंची चला रही हैं। आईआईएफएल सिक्योरिटीज के उपाध्यक्ष (कमोडिटी एवं करेंसी) अनुज गुप्ता ने हिन्दुस्तान को बताया कि बीते एक साल में अधिकांश कमोडिटी की कीमतों में बड़ा उछाल आया है। इसके चलते एफएमसीजी कंपनियों की उत्पादन लगात बढ़ी है। इसलिए कंपनियां उत्पाद को हल्का कर मुनाफा को बरकरार रखने की कोशिश कर रही है।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।